भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1658
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2015 को दिया जाना है

विद्युत उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने की योजना

1658. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/स्कीम तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारे देश में विश्व-स्तरीय मानकों को हासिल करने के लिए पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। भारी उद्योग विभाग ने घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के भावी विकास को बढ़ावा और सहायता देने तथा उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तथा आईईईएमए की सहायता से भारतीय इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग मिशन प्लान 2012-2022 तैयार किया है।

(ख): 24 जुलाई, 2013 को शुरू किए गए इस मिशन प्लान में घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के विकास को गति देने और उसे जारी रखने के लिए सभी हितधारकों के प्रयासों को संचालित, समन्वित और उनमें तालमेल कायम करने की अपेक्षा की गई है। इस मिशन प्लान में व्यक्त विजन 2022 का उद्देश्य "इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत को पसंदीदा देश बनाना और निर्यातों तथा आयातों में संतुलन कायम रखते हुए उत्पादन को 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचाना है।" मिशन प्लान में कार्रवाई हेतु पांच मुख्य क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं: (i) उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता; (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन; (iii) कौशल विकास; (iv) निर्यात; और (v) अव्यक्त मांग का रूपान्तरण।

सभी पांच मुख्य क्षेत्रों में, मिशन प्लान ने घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग की वर्तमान स्थिति/ध्यान देने योग्य क्षेत्रों की पहचान की है। ध्यान देने योग्य प्रत्येक क्षेत्र के लिए सरकार और उद्योग सहित अलग-अलग हितधारकों द्वारा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और उसका विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक और नीतिगत उपायों हेतु विस्तृत संस्तुतियां की गई हैं।

मिशन प्लान की शुरूआत के बाद, डेढ़ साल के दौरान की गई प्रगति की दिशा में मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत संस्तुत विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने के लिए एक सशक्त और समान दृष्टिकोण तैयार करने हेतु दो अंतर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) गठित किए गए थे। आईएमजी के सदस्यों में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग के प्रतिनिधि और आईईईएमए शामिल हैं।

अंतर्मंत्रालयी समूहों की तीन बैठकें 28 अक्टूबर, 2013, 22 अप्रैल, 2014 और 20 फरवरी, 2015 को हुई हैं और अन्य मुद्दों के अलावा इन बैठकों में आयातित उपकरण से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू विनिर्माणकर्ताओं हेतु भारत में एकसमान अवसर उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने, परीक्षण सुविधाओं के स्तरोन्नयन, उत्पादन रेटिंग्स और विशिष्टताओं के मानकीकरण, न्यायोचित संविदा शर्तों, निर्यात की कारोबार लागतों में कटौती, उद्योग पहलों और निर्यात संबंधी तकनीकी अवरोधों का निवारण करने, किए जाने वाले अध्ययनों, इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी विशेषज्ञ समिति, कौशल विकास, विद्यार्थियों द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया गया।

******